अनुदान संख्या 66 – समुद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय
GRANT No. 66–MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	6,00,00	9,00,00	5,84,37	–3,15,63
पूरक	Supplementary	3,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,27,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		1,00,00	31,83	–68,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (315.63 लाख रु.) दिसम्बर, 2004 में प्राप्त किए गए 300.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (327.00 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.315.63 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.300.00 lakhs obtained in December,2004 and constituted 35 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.327.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	480.00	246.00	279.25	+33.25
पु.	R.	–234.00			

(I) 110.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - समुद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय'' के अंतर्गत 192.58 लाख रु. की बचत (470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान दावों के प्राप्त न होने की वजह से परिसरों और सम्बद्ध सेवाओं के किराए की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत 68.17 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत थी।

(I) Provision of Rs.110.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Overseas Indian Affairs" – saving of Rs.192.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.470.00 lakhs) was due to non-payment of rent of the premises and allied services owing to non-receipt of claims during the year.

2. In the capital section of the grant, saving of Rs.68.17 lakhs occurred under one head constituting 68 percent of the sanctioned provision.